



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 15 पटना, बुधवार, 21 चैत्र 1940 (श0)
11 अप्रील 2018 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-4	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---	भाग-9—विज्ञापन ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 5-5
भाग-4—बिहार अधिनियम ---	पूरक ---
	पूरक-क 6-9

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

2 अप्रैल 2018

सं० 6/प्रो०-06-05/2016-1008/वा०कर—बिहार वित्त सेवा संवर्ग के वाणिज्य-कर उपायुक्त (अपुनरीक्षित वेतनमान् रु० 15600-39100 + ग्रेड पे रु० -7600) (पुनरीक्षित वेतनमान् स्तर-12 रु० 78800-209200) कोटि से वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपुनरीक्षित वेतनमान् रु० 37400-67000+ग्रेड पे रु० -8700) (पुनरीक्षित वेतनमान् स्तर-13 रु० 118500-214100) कोटि में निम्नलिखित पदाधिकारी को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	बैच संख्या	वरीयता क्रमांक 2014
1	2	3	4
1.	श्री शैलेन्द्र कुमार	36वीं	103
2.	श्री प्रकाश चन्द्र झा	36वीं	104
3.	श्री अमिताभ मिश्र	36वीं	105
4.	श्री प्रणव बोध रूंगटा	36वीं	106
5.	श्री आनन्द झा	36वीं	107

2. उपरोक्त प्रोन्नतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-4800 दिनांक 01.04.2016 की कंडिका-11(iv) में निहित शर्तों के अधीन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन SLP (C) संख्या. 29770/2015, बिहार राज्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

3. प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जनक राम, उप-सचिव।

2 अप्रैल 2018

सं० 6/प्रो०-06-07/2016-1009/वा०कर—बिहार वित्त सेवा संवर्ग के वाणिज्य-कर पदाधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान् रु० 15600-39100 ग्रेड-पे रु० 5400, नया वेतनमान् स्तर-09 रु० 53100-167800) कोटि से वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त (अपुनरीक्षित वेतनमान् रु० 15600-39100) ग्रेड-पे रु० 6600, (नया वेतनमान् स्तर-11 रु०-67700-208700) कोटि में भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक/आर्थिक लाभ सहित निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रोन्नति दी जाती है:-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वरीयता क्रमांक 2014	बैच संख्या	प्रोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित तिथि (वैचारिक प्रोन्नति)	आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति की तिथि
1.	श्री रमेश कुमार दास (अनु०जाति)	233	40वीं	01.04.14	01.04.14 से सहायक आयुक्त कोटि में
2.	श्री अरविन्द कुमार उपाध्याय	268	द्वितीय सीमित	31.05.14	31.05.14 से सहायक आयुक्त कोटि में
3.	श्री विकाश कुमार पाण्डेय	289	48वीं से 52वीं	29.11.16	29.11.16 से सहायक आयुक्त कोटि में
4.	श्री राजीव रंजन प्रसाद	297	48वीं से 52वीं	29.11.16	29.11.16 से सहायक आयुक्त कोटि में

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वरीयता क्रमांक 2014	बैच संख्या	प्रोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित तिथि (वैचारिक प्रोन्नति)	आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति की तिथि
5.	श्री मनीष कुमार बिहारी	299	48वीं से 52वीं	21.06.16	14.07.16 से सहायक आयुक्त कोटि में
6.	श्री मजीद अहमद	300	48वीं से 52वीं	26.09.17	26.09.17 से सहायक आयुक्त कोटि में
7.	श्री आमीर नैय्यर	301	48वीं से 52वीं	26.09.17	26.09.17 से सहायक आयुक्त कोटि में
8.	श्रीमती रीता सिंह	305	48वीं से 52वीं	21.06.16	30.06.16 से सहायक आयुक्त कोटि में

2. उपरोक्त प्रोन्नतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या—4800 दिनांक 01.04.2016 की कंडिका-11(iv) में निहित शर्तों के अधीन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन SLP (C) संख्या. 29770/2015, बिहार राज्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
जनक राम, उप—सचिव।

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

9 अप्रैल 2018

सं० 18/वि०1-06/2018/99—वित्त विभाग के निदेशानुसार राज्य के सम्पूर्ण वित्तीय कार्य को **Online** करने हेतु **CFMS** प्रणाली का कार्यान्वयन दिनांक 01.04.2018 से किया जाना है। **CFMS** के अंतर्गत **e-billing** एवं **Allotment Module** विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को **Online** आवंटन वितरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। इन कार्यों के सुगमता पूर्वक संचालन हेतु वित्त विभाग द्वारा निदेश दिया गया है।

2. वित्त विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-84 के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की संख्या निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

(i) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत समस्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्य से मुक्त करते हुए यह कार्य जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) से सम्पादित कराने का निर्णय लिया गया है।

(ii) प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत अबतक सभी प्रखण्डों के मुख्यालय अवस्थित मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया गया था। इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जिला में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) जो पूर्व से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित है, को अपने पूर्व के दायित्वों के अतिरिक्त जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से संबंधित मामलों का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का कार्य निष्पादित करेंगे।

(iii) शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय के अंतर्गत **DIET** (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) के प्राचार्य, **PTEC** (प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय) के प्राचार्य, **BIET** (प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) के प्राचार्य एवं **CTE** (अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय) के प्राचार्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित थे। विचारोपरान्त यह मत गठित किया गया कि शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय से संबंधित जिला में अवस्थित **DIET** (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) के प्राचार्य ही शोध एवं प्रशिक्षण से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का कार्य निष्पादित करेंगे।

3. मुख्यालय एवं प्रमण्डल स्तर पर पूर्व से घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यथावत् रहेंगे।

4. इस आदेश के प्रवृत्त होने के पूर्व उपरोक्त कडिका-2 (i), (ii) एवं (iii) एवं कडिका-3 में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ही निकासी एवं व्ययन का कार्य किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचनाएँ, आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

5. प्रस्ताव में वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

6. इस अधिसूचना में माननीय शिक्षा मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार, निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

परिवहन विभाग

अधिसूचना
26 मार्च 2018

सं० 05/स्था० (DTO)-30/2013(खण्ड-1)/2134—श्री मनोज कुमार साही, जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णियाँ को जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। कार्यहित में इनके स्थान पर श्री अमरेन्द्र कुमार पंकज, जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार राय, उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 3—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि

सूचना

No. 501—I, Kalpana Kumari, W/o Bhushan Kumar, R/o Mo. + PS- Purbi Ramkrishna Nagar (Near NTPC colony), PO- Sampatchak, Distt.-Patna-27, do hereby solemnly declare that I was known as Kalpana Sinha. But now I have changed my surname from 'Sinha' to 'Kumari' and now I will be known as "Kalpana Kumari". I am self responsible for this affidavit. Affidavit No. 4260, dated 28.02.2018.

Kalpana Sinha.

सं० 502—मैं हेमंत केसरी (HEMANT KESRI) पिता स्व० सत्यदेव केसरी, 261/65, न्यू जक्कनपुर, पटना-1, बिहार, शपथ संख्या 22657, दिनांक 15-12-2017 द्वारा सूचित करता हूँ कि मैं अब हेमन्त कुमार केसरी (HEMANT KUMAR KESRI) के नाम से जाना जाऊंगा।

हेमंत केसरी।

No. 502—I, Hemant Kesri S/o Late Satyadeo Kesri R/O 261/ 65 near Niyogi villa, New Jakkanpur, P.O+P.S – Jakkanpur, District Patna -1 declare vide Affidavit no-22657 dated 15.12.17 that now onwards I shall be known as Hemant Kumar Keshri.

Hemant Kesri.

No. 503—I, Bhushan Kumar, S/o Ramkishun Prasad, R/o Mo. + PS- Purbi Ramkrishna Nagar (Near NTPC colony), PO- Sampatchak, Distt.-Patna-27, do hereby solemnly declare that I was known as Bhushan Prasad. But now I have changed my surname from 'Prasad' to 'Kumar' and now I will be known as "Bhushan Kumar". I am self-responsible for this affidavit. Affidavit No. 4261, dated 28.02.2018.

Bhushan Prasad.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 3—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

श्रम संसाधन विभाग

आदेश

2 अप्रैल 2018

सं0 5/आर०एल०-40-37/2015 श्र0सं0-1517-श्री मृत्युंजय कुमार झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बरियारपुर, मुंगेर तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी-सह-क्रय केन्द्र प्रभारी, बाँसी (बाँका) को मूल रूप से पैक्सो एवं किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर धान क्रय कर भंडारित करने तथा समय-समय पर राज्य खाद्य निगम कार्यालय से प्राप्त SIO के विरुद्ध मिलरों को धान हस्तगत कराने का दायित्व दिया गया था, जबकि वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्त अंतिम प्रतिवेदनानुसार, श्री झा के द्वारा कुल 70,603.93 क्विंटल धान का क्रय किया गया था, जिसके विरुद्ध राज्य खाद्य निगम द्वारा निर्गत SIO के अनुसार, मात्र 69,889.03 क्विंटल धान ही विभिन्न मिलरों को हस्तगत कराया जा सका।

इस प्रकार श्री झा के द्वारा 714.90 क्विंटल धान मिलरों तक नहीं पहुँचाया जा सका, जिसके फलस्वरूप सरकार को लगभग 13,60,547/- (तेरह लाख, साठ हजार, पाँच सौ सैंतालीस) रू0 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गई और 714.90 क्विंटल धान की क्षति/गबन के लिए श्री झा को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाते हुए उनके विरुद्ध प्रपत्र "क" के तहत गठित आरोपों के संदर्भ में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2011-12 सहित वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अन्तर्गत प्रमादी मिलरों से सी0एम0आर0 जमा नहीं करने के कारण इनके विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करने के साथ प्राथमिकी भी दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। विदित हो कि इस मामले की सुनवाई एवं अनुश्रवण जनहित याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी की जा रही है, जबकि आलोच्य मामले में तत्कालीन विभागीय सचिव, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा श्री झा सहित अन्य श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करते हुए प्रपत्र "क" के तहत आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निदेश दिया गया।

उक्त क्रम में तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बाँका, उप श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक), भागलपुर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बाँका एवं वरीय प्रभारी-सह-अपर समाहर्ता, बाँका के प्रतिवेदन के आधार पर जिला पदाधिकारी, बाँका के द्वारा वर्ष 2011-12 धान अधिप्राप्ति कार्य में दोषी पाये गये श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों यथा-श्री झा सहित अन्य दो के विरुद्ध प्रपत्र "क" के तहत आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा श्रमायुक्त, बिहार, पटना से किया गया।

इसी बीच, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बाँका के द्वारा श्री मृत्युंजय कुमार झा, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी-सह-क्रय केन्द्र प्रभारी, बाँसी सहित श्री सौरभ कुमार चौधरी, कृषि समन्वयक के विरुद्ध सरकारी पद पर पदस्थापित रहते हुए अपराधिक षडयंत्र के तहत कुल 714.90 क्विंटल धान का गबन किये जाने को घोर वित्तीय अनियमितता एवं आपराधिक कृत्य मानते हुए उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की सुसंगत धाराओं के तहत नामजद प्राथमिकी (39/2015) भी दर्ज करायी गई।

श्री झा के द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर के माध्यम से अंकित किया गया है कि दिनांक 07.05.13 को गुरुधाम स्थित धान क्रय केन्द्र से धान की बोरी चोरी हो जाने के संबंध में थानाध्यक्ष, बाँसी को सूचित किया गया, परन्तु उनके द्वारा धान की बोरी की मात्रा को स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि थानाध्यक्ष, बाँसी धान की बोरी की चोरी की सूचना दिये जाने की मात्र औपचारिकता का ही निर्वहन किया गया है और सर्वाधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इसे मात्र सूचना के रूप से देते हुए धान केन्द्र पर चौकीदार प्रतिनियुक्ति करने का अनुरोध किया गया एवं उक्त

चोरी के संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया, जबकि वर्णित चोरी से सीधे तौर पर सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचायी जा रही थी, इस प्रकार, श्री झा के द्वारा धान की चोरी के संबंध में थानाध्यक्ष मात्र को सूचित कर दिये जाने से क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में उनकी जबाबदेही की गंभीरता कम नहीं हो जाती है।

श्री झा के समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के द्वारा सर्वप्रथम यह अंकित किया गया है कि संचालन पदाधिकारी के द्वारा सुनवाई में उभय पक्ष को मौका नहीं दिया गया, जिसके अनुसार, विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बाँका अथवा उनके प्रतिनिधि को बुलाया जाना था, ताकि लगाये गये आरोपों का दस्तावेजी सत्यापन किया जा सके, परन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा इसकी अनदेखी कर एकतरफा मंतव्य दे दिया गया और आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित कर दिया गया।

उक्त माध्यम से श्री झा के द्वारा संचालन पदाधिकारी के संचालन प्रतिवेदन (जाँच प्रतिवेदन) की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न उठाये गये हैं, जबकि विभागीय कार्यवाही का संचालन एक अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही के समान है, जबकि उभय पक्ष के रूप में सरकारी अथवा निगम का पक्ष रखने के लिए नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी सुनवाई के दौरान उपस्थित थे। उक्त सुनवाई के दौरान अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए श्री झा को विभिन्न तिथियों यथा—07.09.15, 21.09.15, 15.10.15, 23.11.15, 12.12.15, 11.01.16 एवं 27.01.16 को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। इस प्रकार, उक्त कार्यवाही में CCA Rules का कोई उल्लंघन किये जाने संबंधी श्री झा का दावा तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

श्री झा के द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के माध्यम से धान की क्षति/गबन के संबंध में मुख्य रूप से यह भी तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है कि लगभग 70 से 80 प्रतिशत धान की मात्रा गोदाम के बाहर परती जमीन पर खुले आसमान के नीचे जिला पदाधिकारी के आदेश पर भंडारित किया गया था, जिसके फलस्वरूप धान लावरिस अवस्था में कड़ी धूप, वर्षा, आँधी, ओलावृष्टि एवं खुले आसमान में रहने तथा चोरी होने के कारण धान की क्षति हुई।

श्री झा के उपरोक्त कथन से वर्णित परिस्थितिजन्य कारणों से धान के व्यापक क्षति की पुष्टि होती है, परन्तु उक्त क्षति के लिए श्री झा को सीधे तौर पर जिम्मेवार नहीं मानने का कोई युक्तिसंगत अवसर प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि श्री झा के द्वारा क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते धान की क्षति/चोरी अथवा गबन के संबंध में संचालित विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव-बयान के तहत प्राथमिकी दर्ज किये जाने का उल्लेख भी तथ्यगत नहीं है, जबकि स्पष्ट है कि श्री झा के द्वारा ऐसी कोई प्राथमिकी दर्ज ही नहीं की गई, बल्कि उक्त चोरी की सूचना देते हुए धान क्रय केन्द्र पर चौकीदार प्रतिनियुक्त करने का मात्र का अनुरोध किया गया था।

इस प्रकार श्री झा उक्त धान की चोरी को रोकने में भी विफल रहे और दूसरी ओर जिला प्रबंधक मात्र को सूचित कर अपने कार्य दायित्व का निर्वहन कर लिया गया, परन्तु उसके अतिरिक्त श्री झा के द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, जिससे धान की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष क्षति/गबन को रोका जा सके, जबकि ये उनकी स्वाभाविक जिम्मेवारी थी।

अपने द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के माध्यम से यह तर्क रखा जाना कि जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बाँका के द्वारा धान खरीद हेतु समुचित व्यवस्था नहीं किये जाने की स्थिति में संचालन प्रतिवेदनानुसार गबन कार्य में उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए का तर्क स्वयं के दायित्व को स्थानांतरित किये जाने का प्रयास मात्र प्रतीत होता है, क्योंकि जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बाँका के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने का दायित्व श्रम विभाग पर न होकर उनके प्रशासी विभाग का है।

जहाँ तक सहकारिता विभाग के द्वारा प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी-सह-क्रय केन्द्र प्रभारी, अमरपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोप से संचालन पदाधिकारी के द्वारा मुक्त कर दिये जाने के संदर्भ का प्रश्न है तो स्पष्ट है कि आरोपों की गंभीरता एवं सन्निहित परिस्थितियों को दृष्टिपथ में रखते हुए उनके अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया गया, जिसके अन्य समान मामलों में भी अक्षरशः लागू होने का तर्क भी असंगत प्रतीत होता है।

श्री झा के द्वारा यह भी पक्ष रखा गया है कि उनके विरुद्ध गठित प्रपत्र “क” के तहत 714.90 क्विंटल धान की क्षति/गबन का आरोप साक्ष्य आधारित नहीं है, क्योंकि प्रभार प्रतिवेदनानुसार 692.00 क्विंटल धान क्षतिग्रस्त अवस्था में एवं 174.80 क्विंटल धान सुरक्षित अवस्था में गोदाम का प्रभार दिया गया है और नीलाम पत्र वाद सं०-53/2014-15 में उनके विरुद्ध रु० 4,39,355/- राशि ही उनसे संबंधित है, जिसे श्री झा के द्वारा प्रकारांतर से सन्निहित आरोप की स्वीकारोक्ति माना जा सकता है और जहाँ तक सन्निहित आरोप में धान की मात्रा में परिवर्तन होने का प्रश्न है तो उक्त स्थिति में बदलाव होने के बावजूद सन्निहित क्षति अथवा गबन संबंधी आरोप की गंभीरता को कमतर आँका नहीं जा सकता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में तथापि प्रश्नगत मामलों में उप श्रमायुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के तहत श्री झा के विरुद्ध गठित सारे आरोप प्रमाणित पाये गये हैं और प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में निर्गत द्वितीय कारण पृच्छा के बिन्दु पर श्री झा के समर्पित स्पष्टीकरण के माध्यम से ऐसा कोई ठोस तथ्य अथवा अकाट्य साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर सन्निहित आरोपों को खंडित किया जा सके। इस प्रकार, श्री झा के द्वारा किये जा रहे किसी भी दावों का संपोषण नहीं होता है।

तदालोक में सम्यक् विचारोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों का दोषी पाते हुए श्री झा के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2005 के भाग-V के नियम 14 (11) के तहत निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए श्री झा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है:-

1. श्री मृत्युंजय कुमार झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बरियारपुर, मुंगेर तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी-सह-क्रय केन्द्र प्रभारी, बौसी, बांका, वरीयता क्रमांक-371, जन्म तिथि 15.08.68, नियुक्ति तिथि 07.04.1998 को सरकारी सेवा से बर्खास्त (Dismiss) किया जाता है।

श्री झा को उनके भविष्य निधि तथा ग्रुप बीमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि भुगतये नहीं होगा।

आदेश से,
गोपाल मीणा, श्रमायुक्त।

कृषि विभाग

आदेश
23 फरवरी 2018

सं० 2 (गो०)सी०-05-03/2008-125 कृ०—श्री सोहन प्रसाद यादव, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया के विरुद्ध दायित्व का निर्वहन नहीं करने, आदेश का उल्लंघन करने, खाद बीज की उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति उपलब्ध नहीं कराने, राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन की कार्यकारिणी के निर्णयों का अनुपालन नहीं करने, प्राथमिकता वाली योजनाओं में इनकी उपलब्धता शून्य रहने आदि आरोपों लिए निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालनोपरांत सभी प्रक्रिया पूर्ण कर विभागीय अधिसूचना संख्या-482 दिनांक 10.10.2012 द्वारा श्री सोहन प्रसाद यादव, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली-2007 के नियम-14 (viii) के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 2966 दिनांक 31.08.2007 की कंडिका-2 के आलोक में निम्नतर कालमान वेतन कोटि पद या सेवा में अवनति अर्थात् बिहार कृषि सेवा कोटि-I (शष्य) के पद से बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-1 (शष्य) के पद पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष वेतनमान 5000-8000 (अपुनरीक्षित) में स्थायी तौर पर पदावनत करने का दण्ड संसूचित किया गया।

उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री वेदनारायण सिंह, महामंत्री बिहार कृषि सेवा संघ एवं श्रीमती कुंती देवी, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा, अत्तरी, गया का "भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के आलोक में पदावनति के आदेश पर पुनर्विचार करने के संबंध में" आवेदन प्राप्त हुआ। उक्त पर कार्यवाई करते हुए विभागीय पत्रांक 627 दिनांक 21.12.2016 द्वारा श्री यादव से कतिपय कागजात/अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया जो श्री यादव द्वारा दिनांक 10.01.2017 को उपलब्ध कराया गया।

उक्त पर कार्यवाई के क्रम में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया एवं सम्यक समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-482 दिनांक 10.10.2012 में संशोधन करते हुए श्री सोहन प्रसाद यादव, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया सम्प्रति सहायक कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि कार्यालय, वैशाली, हाजीपुर को निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया:-

1. नियुक्ति के समय के मूल कोटि के पद पर स्थायी रूप से पदावनत।
2. निलंबन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

लिये गये निर्णय के आलोक में श्री सोहन प्रसाद यादव, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया सम्प्रति सहायक कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि कार्यालय, वैशाली, हाजीपुर को निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किये जाते हैं:-

1. नियुक्ति के समय के मूल कोटि के पद पर स्थायी रूप से पदावनत।
 2. निलंबन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
विनोद रजक, अवर सचिव।

आदेश
27 मार्च 2018

सं० 2(गो०)सी०-2-58/14-201 कृ०—श्री कृष्णा नन्द चक्रवर्ती, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल —सह-प्रभारी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, अरवल सम्प्रति परियोजना निदेशक (आत्मा), पटना के विरुद्ध लक्ष्य के विरुद्ध एक भी कीटनाशी नमूना संग्रह नहीं कर स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता एवं आदेश उल्लंघन के आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-75 दिनांक 16.02.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय समीक्षोपरांत सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कृष्णा नन्द चक्रवर्ती, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल-सह-प्रभारी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, अरवल सम्प्रति परियोजना निदेशक (आत्मा), पटना को आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

तदालोक में श्री कृष्णा नन्द चक्रवर्ती, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल-सह-प्रभारी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, अरवल सम्प्रति परियोजना निदेशक (आत्मा), पटना को आरोप से मुक्त किया जाता है।

आदेश से,
विनोद रजक, अवर सचिव।

आदेश

27 मार्च 2018

सं० 2(गो०)सी०-6-8/2013-196 कृ०-श्री राम ईश्वर प्रसाद, तत्कालीन जिला उद्यान पदाधिकारी, गया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना प्रमंडल, पटना जिन्हें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना की टीम के द्वारा 7,000/- (सात हजार) रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किये जाने के पश्चात् विभागीय अधिसूचना संख्या-184 दिनांक 16.07.2013 द्वारा दिनांक 04.07.2013 से कारावास में रहने अवधि तक के लिए निलंबित किया गया।

दिनांक 18.10.2013 को कारावास से मुक्त होने के पश्चात् दिनांक 21.10.2013 के योगदान के पश्चात् विभागीय आदेश ज्ञापांक-325 दिनांक 30.12.2013 द्वारा इनका योगदान दिनांक 21.10.2013 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया।

विभागीय अधिसूचना संख्या-331 दिनांक 31.12.2013 के द्वारा श्री प्रसाद को उनके योगदान स्वीकृति की तिथि दिनांक 21.10.2013 के प्रभाव से पुनः निलंबित किया गया।

सी०डब्लू०जे०सी०संख्या-15238/2017 राम ईश्वर प्रसाद, बनारस बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 07.02.2018 एवं दिनांक 15.02.2018 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय-निर्णय के अनुपालन में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रसाद को तात्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा उपरोक्त लिये गये निर्णय के आलोक में श्री राम ईश्वर प्रसाद, तत्कालीन जिला उद्यान पदाधिकारी, गया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना प्रमंडल, पटना को तात्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

2. विभागीय कार्यवाही चलता रहेगा।

3. विभागीय कार्यवाही में अंतिम निर्णय पारित होने के पश्चात् निलंबन-अवधि के वेतनादि के भुगतान के बिन्दू पर निर्णय लिया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
विनोद रजक, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 3-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>